"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021 — आषाढ 29, शक 1943

## श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2021

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7/2020/16.— प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन कर डाटा बेस तैयार कर बेहतर रोजगार की तलाश हेतु सुगम एवं सुरक्षित प्रवास करने हेतु विभिन्न विभाग यथा—राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, रोजगार नियोजन, उद्योग शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त एवं गृह आदि के समन्वय से श्रम विभाग द्वारा छ०ग० राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 निम्नवत बनाई जाती है:--

## छ.ग. राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020

#### 1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों व वनोपज से सम्पन्न कृषि प्रधान राज्य है। यहां के निवासियों की आजीविका का आधार कृषि, वनोपज व मजदूरी है। छत्तीसगढ़ में कृषि का स्वरूप एकल फसली होने से लघु एवं सीमांत कृषक व कृषि मजदूर अन्य राज्यों में प्रवास पर जाते है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय युवाओं का कौशल उन्नयन, कृषि व वन उपज एवं पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे है, परन्तु बेहतर रोजगार एवं अधिक आय की उम्मीद में श्रमिक दूसरे राज्यों में कार्य हेतु प्रवास पर जाते है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक अन्य राज्यों में ईटट् निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, आदि क्षेत्र में मजदूरी कार्यों के लिये प्रवास करते है, जो कि मौसमी, आकिस्मक अथवा पूर्णकालिक स्वरूप का होता है।

प्रवासी श्रमिक राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण आधार है। प्रवासी श्रमिक की प्रवासित राज्य एवं मूल निवास राज्य के विकास में समुचित भागीदारी होती है, इसके बावजूद प्रवासित राज्य में प्रवासी श्रमिकों को शोषण एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

#### 2. वर्तमान परिदृश्य में प्रवास नीति की आवश्यकता

वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों हित संरक्षण हेतु अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 प्रभावशील है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन को कोई प्रावधान नहीं होने से उनके आकड़े उपलब्ध नहीं रहने के कारण कोरोना वायरस (कोविड – 19) संक्रमणकाल में लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में प्रवासी श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाईयों को सामना करना पड़ा। उक्त संकटकालीन स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के प्रवासित राज्य एवं स्थानीय

राज्य में प्रवासी श्रमिकों के निवास/नियोजन/नियोजक इत्यादि की जानकारी नहीं होने से उन्हें आवश्यक तात्कालीक सहायता उपलब्ध कराने एवं घर वापसी में शासन को प्रवासित राज्य से समन्वय स्थापित करने में कठनाईयाँ उपस्थित हुई, जिससे प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक मदद सही समय पर पहुंचाने में कठिनाई हुई।

छत्तीसगढ़ का श्रमिक भारत के किसी भी क्षेत्र में भयमुक्त श्रम कर पाये, ऐसा स्वस्थ्य वातावरण तैयार करना जरूरी है, जिसमें श्रमिक अपनी क्षमता एवं अवसरों के अनुरूप आजीविका निर्वहन कर सके। श्रमिकों के लिये स्वस्थ्य वातावरण एवं उनके हकों की सुरक्षा के लिये राज्यों के मध्य साझा—समझ विकसित करना, दायित्वों को निर्धारित करना तथा प्रक्रिया स्थापित करना आज की जरूरत है, तािक आपातकालीन परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण हेतु बने श्रम कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन कर उनके हित संरक्षित किये जा सके एवं उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से भी उन्हें लाभावित किया जा सके।

## 3. उद्देशिका

- 3.1 कार्यस्थल पर भयमुक्त वातावरण तैयार करना ताकि श्रमिकों की गरिमा सूनिश्चित हो।
- 3.2 समता व समानता के मूल्यों पर प्रवासी श्रमिकों का क्षमता विकास तथा रोजगार के समुचित अवसर स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध कराना।
- 3.3 प्रवासी श्रमिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिये वर्तमान संचालित व्यवस्थाओं में सरलता एवं सुगमता लाना।
- 3.4 श्रिमकों से संबंधित जानकारी एवं सूचनाओं का प्रबंधन सुदृढ़ करना।
- 3.5 प्रवासी श्रमिकों की छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदारी बढ़ाना तथा उनके कल्याण व सुरक्षा की रणनीति निर्माण करना।

#### 4. प्रवासी श्रमिकों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिबद्धता

- 4.1 प्रवासी श्रमिकों की जागरूकता एवं दक्षता विकसित करना।
- 4.2 राज्यों के साथ समन्वय एवं सहयोग से श्रमिकों में परामर्श के माध्यम से समझ विकसित करना।
- 4.3 कार्यस्थल में प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधायें का लाभ सुनिश्चित करना।
- 4.4 कार्यस्थल पर महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के श्रमिकों का हक संरक्षण।
- 4.5 श्रमिक कल्याण हेतु बजट की समुचित व्यवस्था।
- 4.6 आकस्मिक परिस्थिति में प्रवासी श्रमिक की सहायता एवं सूचना प्रबंधन की व्यवस्था।
- 4.7 प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- 4.8 प्रवासी श्रमिकों को प्रवासित राज्य के श्रमिक के बराबर हक एवं सुविधायें सुनिश्चित करना।

#### 5. लक्ष्य

- 5.1 समस्त प्रवासी श्रमिकों / संभावित प्रवासी श्रमिकों सर्वेक्षण एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना।
- 5.2 प्रवासी श्रमिकों के। पहचान पत्र, श्रम पंजीयन, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 5.3 प्रवासी श्रमिकों के गंतव्य कार्यस्थलों / क्षेत्रों की पहचान कर सम्बन्धित राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (M.O.U.) के माध्यम से कार्यस्थलों पर श्रमिकों के हकों को सुरक्षित करना।
- 5.4 सर्वेक्षित डेटा के आधार पर विश्लेषण कर प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेत् कार्ययोजना तैयार करना।
- 5.5 प्रवासी मजदूरों के लिये पात्रता के आधार पर राज्य व राज्य के बाहर शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराना।

#### 6. प्रवासी श्रमिक से आशय

ऐसा श्रमिक जो कार्य के लिये अपने निवास स्थान से अन्तर्राज्य या अन्तःराज्य में स्वैच्छा या किसी ठेकेदार/एजेन्ट के माध्यम से परिवार का एक सदस्य या सम्पूर्ण परिवार या एक से अधिक सदस्य प्रवास करते है। उक्त प्रवास मौसमी, स्थायी या अस्थायी प्रकृति का हो सकता है।

#### 7. प्रवासी श्रमिकों का हक

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, भारतीय नागरिक (प्रवासी श्रमिक) को भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदाय करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप में उन्हें जीवन जीने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, ताकि जीवन के अधिकार के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में मानव गरिमा को अपनाया जा सके।.

## प्रवासी श्रमिकों के निम्नलिखित हकों का संरक्षण :--

- 7.1 व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं अवसरों के अनुसार किसी भी स्थान पर कार्य करने की स्वतंत्रता।
- 7.2 छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्रता अनुसार यथावत दिया जाना।
- 7.3 केन्द्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदाय लाभों को यथावत रखने हेतु प्रयास।

#### स्रोत पर किये जाने वाले कार्य

## 8. श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण एवं सूचनाओं का प्रबंधन

- 8.1 श्रमिक पंजीयन की प्रक्रिया में सरलता लाना।
- 8.2 प्रवासी श्रमिकों की पहचान के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता, स्वास्थ्य पंजीयन कार्ड, श्रमिक पंजीयन इत्यादि की उपलब्ध सुनिश्चित करना।
- 8.3 प्रवास/पलायन पंजी का पंचायत एवं वार्डवार डिजिटल प्रणाली के माध्यम में संधारण।
- 8.4 प्रवासी श्रमिक नियोजक / ठेकेदार / एजेंट का प्रचलित श्रम अधिनियमांतर्गत पंजीयन।
- 8.5 प्रवासी श्रमिकों का प्रचलित श्रम कानून के अंतर्गत हित संरक्षण।

## 9. सूचना प्रबंधन : श्रमिक सूचना पटल

- 9.1 हेल्पलाईन की स्थापना।
- 9.2 शिकायत निवारण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण।
- 9.3 श्रमिक सूचना पटल के माध्यम से श्रमिकों, नियोजकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रवासित राज्य शासन के साथ समन्वय एवं सूचनाओं का प्रबंधन कर, श्रमिकों का हित संरक्षण।

## 10. श्रमिकों के कौशल का आंकलन एवं कौशल विकास

- 10.1 प्रवासी श्रमिक के कौशल का आंकलन कर कौशल विकास की कार्ययोजना बनाना।
- 10.2 एकाधिक कौशल विकास पर जोर देना।
- 10.3 श्रमिकों की दक्षता का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना।

## 11. श्रमिकों की कानूनी, वैधानिक व वित्तीय साक्षरता पर समझ विकसित करना

- 11.1 प्रवासी श्रमिक को उनके अधिकारों की सुरक्षा के कानूनी व्यवस्था की जानकारी देना।
- 11.2 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्त विभागों (राजस्व, पंचायत, श्रम, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा आदि) को संवेदनशील करना।
- 11.3 ठेकेदारों, नियोक्ताओं एवं श्रम संगठनों को संवेदनशील करना।
- 11.4 प्रवास के पूर्व श्रमिकों की वित्तीय प्रबंधन, बैंक व्यवहार, एटीम से राशि निकालने, मोबाईल बैंकिंग, मजदूरी दर एवं भुगतान का हिसाब किताब पर समझ विकसित करना।
- 11.5 सामुदायिक प्रचार माध्यम से प्रवासी श्रमिक हित संरक्षण सूचनाओं का प्रचार—प्रसार कर जनजागरण करना।

## 12. 'प्रवासी श्रमिक सहायता केन्द्र' (श्रम संसाधन केंन्द्र) स्थापित करना

- 12.1 प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिये विकासखण्ड व जिला स्तर पर 'प्रवासी श्रमिक सहायता केन्द्र' (श्रम संसाधन केन्द्र) का संचालन किया जाना।
- 12.2 श्रम संसाधन केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर श्रम मित्रों का केंडर तैयार किया जावेगा, जो कि श्रम उद्यमी के रूप में कार्य करेंगे।
- 12.3 श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, योजनाओं से श्रमिकों को लाभावित करना, प्रवासी श्रमिकों का हित संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जावेगा।

12.4 श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों को विधिक, वित्तीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

#### 13. विभागीय उत्तरदायित्व

प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक हकों की सुरक्षा, जागरूकता, दक्षता विकास एवं स्वरथ्य वातावरण तैयार करने के लिये विभागीय जवादेही को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- 13.1 राजस्व विभाग प्रवासी श्रमिक नीति के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जिला स्तर पर पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिक पुर्नवास एवं कल्याण के कार्यवाही संपादित करेंगे।
- 13.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रवासी श्रमिक पंजी का संधारण एवं अद्यतीकरण करना तथा प्रवासी श्रमिक को पुर्नवासित कर स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार शासन के योजनांतर्गत उपलब्ध कराना।
- **13.3** कौशल विकास प्राधिकरण प्रवासी श्रमिकों के कौशल का आंकलन एवं कौशल विकास करना तथा दक्षता का प्रमाणीकरण।
- 13.4 रोजगार एवं ि ोजन विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग विभिन्न निर्माण विभागों, उद्योगों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के लिये स्थानीय स्तर पर रोजगार की अवसरों की खोज करना।
- 13.5 समस्त निर्माण विभाग निर्माण कार्यो में ठेकेदारों को स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता से काम उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना।
- 13.6 शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग चिन्हांकित प्रवासी श्रमिकों परिवार के बच्चों को शिक्षण सुविधा निरंतरित करना तथा आवासीय स्कूलों में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता तथा दूसरे राज्यो प्रवास कर चूके बच्चों की पहचान करना सम्बन्धित राज्यों को सूचित करना ताकि गंतव्य स्थानों पर उनको स्कूल में प्रवेश के अवसर मिले।
- 13.7 स्वास्थ्य विभाग प्रवासी श्रमिकों को वर्तमान संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाना तथा कामकाजी महिलाओं के लिये एवं प्रवासी श्रमिक परिवार के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं प्रदाय करना।
- 13.8 महिला एवं बाल विकास विभाग प्रवासी महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिये सखी वनस्टाप केन्द्रों का बेहतर संचालन करना।
- **13.9** गृह विभाग पुलिस थाना स्तर पर 'प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क' शुरू करना जिसमें माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की वैधानिक सहायता प्रदान करना।
- 13.10 श्रम विमाग प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु प्रचलित विभिन्न श्रम कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा अंतर्राज्यीय सहयोग व समन्वय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य करना। श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करना।
- 13.11 नगरीय प्रशासन विभाग नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्लम/श्रमिक बस्तीयों में प्रवासी श्रमिक पंजी का वार्डवार संधारण एवं अद्यतीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में आये श्रमिकों को आवश्यक सुविधायें, प्रचलित योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित करना।
- 13.12 जिला योजना समिति जिला स्तर पर श्रमिक सर्वेक्षण, पंजीयन, कॉल सेन्टर, श्रम संसाधन केन्द्र की निगरानी एवं मूल्यांकन कर श्रमिक कल्याण का पर्यवेक्षण।

#### गंतव्य पर किये जाने वाले कार्य

श्रमिकं गंतव्य स्थान पर असंगठित होते है, छोटे समूह में रहते है तथा जानकारी के अभाव में या काम छुटने के डर से शोषण एवं कठनाईयों का सामना करते है। इस स्थिति में मजदूरों का मनोबल बढ़ाने तथा उनके हकों एवं सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिये गंतव्य स्थलों पर उनकी सुरक्षा के लिये गंतव्य राज्य शासन या स्थानीय संगठन के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त प्रयास किये जायेंगे।

#### 14. श्रम संगठन/ट्रेड युनियन, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी

14.1 मजदूर साथी नेटवर्क — गंतव्य स्थानों पर श्रमिकों की सहायता के लिये संबंधित राज्यों में सक्रिय श्रम संगठन, ट्रेड युनियन, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय प्रशासन इत्यादि को शामिल कर मजदूर साथी नेटवर्क तैयार किया जावेगा। जिसके माध्यम से अंतर्राज्यीय संवाद एवं समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जावेगी।

## 15. मजदूरी दर एवं भुगतान की निगरानी

- 15.1 प्रवासी श्रमिकों को प्रचलित श्रम कानूनों के प्रावधानित लाभ, गंतव्य राज्यों में प्राप्त हो, इस हेतु संबंधित राज्य के प्रशासन से समन्वय बनाये रखना।
- 15.2 पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा संधारित प्रवासी पंजी की जानकारी संबंधित राज्य से साझा कर गंतव्य राज्य में प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण।

## 16. गंतव्य राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास

- 16.1 छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गंतव्य राज्यों के साथ श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये समझौते करने के प्रयास करना।
- 16.2 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंन्द्र सरकार एवं अन्य प्रवासी श्रमिक गंतव्य राज्यों से अनुरोध किया जायेगा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिक जिस राज्य में कार्य कर रहे है, वहां प्रवासी श्रमिकों को केन्द्र की योजनाओं एवं संबंधित राज्य के मुताबिक उनको सेवा, सुविधा व लाभ प्राप्त करने का हक हो।

#### 17. आपातकालीन व्यवस्था

प्रवासी श्रमिक अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थल पर असंगठित स्वरूप में कार्यरत् रहता है, जिससे विभिन्न आपदाओं में उसे शासन के मदद की आवश्यकता पड़ती है। प्रवासी श्रमिकों को मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाईयों सिहत दुर्घटना में आकिस्मिक मृत्यु, बंधक बनाये जाने की परिस्थिति, श्रमिक के हितलाभ नियोजक द्वारा नही दिये जाने की स्थिति इत्यादि. परिस्थियों का सामना करना पड़ता है। चुँकि प्रवासी श्रमिक असंगठित रहते है एवं उनका नियोजन अनियमित होता है, इस लिये संकटकालीन परिस्थिति में संकटापन प्रवासी श्रमिकों की मदद शासन द्वारा अपेक्षित रहती है। अतः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को आकिस्मिक आपातकालीन परिस्थिति में सहायता हेतु विभागों की समन्वय सिति रहेगी, जो कि एक निश्चित कार्ययोजना बनाकर काम करेगी।

#### 18. वित्तीय संसाधन के लिये उपाय

- 18.1 भवन एवं अन्य निर्माण उपकर की वसूली में वर्तमान गैप की पहचान की जायेगी तथा गैप को पूर्ण कर वसूली में वृद्धि के प्रयास करना।
- 18.2 इसके अतिरिक्त अन्य बजट के स्त्रोतों की पहचान व चिन्हाकित करना ताकि श्रम कल्याण के लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध हो सके।
- 18.3 प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिये राज्य शासन के बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना।

श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिये यह नीति बहुत उपयोगी हो सकती है, जिसके क्रियान्वयन में समस्त विभाग, स्वैच्छिक संगठन एवं श्रम संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह नीति अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सिद्ध होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

## अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-7/2020/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10-7/2020/16, दिनांक 19-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

#### Atal Nagar, the 19th July 2021

#### **NOTIFICATION**

No. F 10-7/2020/16.— With Keeping due respect to the interest, welfare and social security of migrant labours, and in search of registration database to improve the employment and living conditions of migrant labours, the Labour Department of Chhattisgarh has made the Migrant Labour policy, 2020 with due recommendations from various departments such as Panchayat & Rural Development department, Skill Development Authorization, Employment Planning, Industry Planning Department, Health, Financing & Housing, etc. which are as follows:-

#### 1. Introduction

Chhattisgarh is the prime state of natural resources and forest produce. Here livelihood of the residents is the basis of agriculture, forest produce, and wages. In Chhattisgarh, due to the nature of agriculture is limited to single cropping, small marginalised farmers or agricultural labourers migrate to other states.

Efforts are being made by the Government of Chhattisgarh to generate skill enhancement of local youth, employment in the area of agriculture and forest produce and animal husbandry, but labourers migrate to other states in the hope of better employment and higher income. Workers from Chhattisgarh migrate to other states for wage work in areas such as brick making, building construction, road construction, domestic work, industry, agriculture, etc. which are of seasonal, casual, or full-time is the character.

Migrant labour is an important foundation of nation-building. The migrant workers have a appropriate participation in the development of the migrant state and the native state, despite this; the migrant workers have to face exploitation & difficulties in the migrant state.

#### 2. Migration in the current scenario

Presently, the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 is effective to protect the interests of the migrant laborers, in which there is no provision for registration of migrant laborers due to the non-availability of their data. Migrant laborers had been faced with extreme difficulties. In the aforesaid condition, the Government found difficulties In the event of lockdown during infection of Coronavirus (Covid- 19). In mean time of disterss situation the information of migrant labours of migrant state and migrant labours of native states tackled with difficulty in providing necessary support and to return to their native, Government had come across with difficulties to establish coordination with the migrant state, which led to difficulty in providing necessary immediate help to the migrant labour.

It is necessary to create a healthy environment in which the labours of Chhattisgarh can work fearlessly in any area of India, wherein the labours can subsistence their livelyhood according to their capacity and opportunities. It is the current need to develop a mutual understanding, for providing the healthy environment and protect the rights of workers, set responsibilities and set up procedures for the states so that in emergency situation, necessary support can be provided to the migrant laborers as well as by better implementation of labor laws, for protection of migrant labours so that their interests can be protected and can be benefited by prevalent scheme for their welfare.

#### 3. Preamble

- 3.1 To create a fearless environment at work so as to ensure dignity of workers.
- 3.2 To provice equity and equality of vaues capacity development for migrant labours and providing appropriate opportunities of employment at local level.
- 3.3 To bring ease and smoothness in present prevalent arrangements to increase access to migrant labour.
- 3.4 To strengthen the management of information and information related to labour.
- 3.5 To increase participation of the migrant labourers in the development of Chhattisgarh and to formulate a strategy for their welfare and security.

#### 4. Chhattisgarh State's Commitment to Migrant Workers

- 4.1 To develop awareness and skills of migrant laborers.
- 4.2 Co-ordination with the States and develop understanding through consultation in the labor force.
- 4.3 Ensuring the benefits of various schemes and facilities of migrant workers at the workplace
- 4.4 Protection of rights of women, children, and labourers of the weaker sections at the workplace. appropriate arrangement of a budget for labor welfare.

- 4.5 Arrangement of assistance and information management of migrant workers in emergent situations.
- 4.6 Providing social security to the migrant laborers and their families.
- 4.7 Ensuring the rights and facilities of the migrant workers equal to the workers of the migrant state.

#### 5. Goals

- 5.1 Preparation of survey and reliable databases for all migrant laborers/probable migrant laborers.
- 5.2 To ensure availability of documents such as identity card, labor registration, bank account, Aadhaar card, etc. to the migrant laborers.
- 5.3 Identifying the destination/work area of the migrant labor and securing the rights of the workers at the workplace through the memorandum of understanding (M.O.U.) with the respective states.
- 5.4 To prepare an action plan for welfare of migrant workers by analyzing on the basis of surveyed data.
- 5.5 Providing benefits under government or territory outside the state and state, based on eligibility for migrant jobs.

#### 6. Migrant laborers

Such a laborer migrates from his / her place of residence in the inter-state or intra-state voluntarily or through a contractor/agent with a member of the family or whole family or more than one member. The said migration can be of a seasonal, permanent, or temporary nature.

#### 7. Rights of migrant laborers

Under Article 19 of the Constitution, Indian citizens (migrant workers) have the right to move freely throughout the territory of India. Article 16 of the Constitution provides There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment. Interpretation by the Supreme Court for Article 21 of the Constitution describes Protection of life and personal liberty No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law so that human dignity can be adopted as an essential component for the right to life.

#### Protection of the following workers in migrant laborers: -

- 7.1 Freedom of a person to work at any place according to his / her disability and opportunity.
- 7.2 The benefits of the schemes of the state of Chhattisgarh should be given as per eligibility.
- 7.3 Efforts are made to maintain the supply benefits under the central schemes or programs.

#### Efforts initiate at source

#### 8. Identification of laborers, registration, and management of information

- 8.1 Simplify the process of labour registration.
- 8.2 Ensure availability of documents of the identity of migrant workers such as Aadhar card, Voter ID card, Ration card, Bank account, Health registration card, labour registration, etc.
- 8.3 Maintenance of migrate/migration register through the Panchayat and Ward wise digital system.
- 8.4 Registration of migrant employer/contractor/agent under Prevailing Labour Act.
- 8.5 Protection of the migrant labourers under the Prevailing Labour Law.

#### 9. Information Management- The Labor Information portal

- 9.1 Establishment of the helpline.
- 9.2 Strengthening the grievance redressal mechanism.
- 9.3 By coordination with the migrant State Government to workers, employers SHG by medium of Shramik Suchana Patal and managing information, for the protection of interest of labour.

#### 10. Estimation of Skill of Labour and Skill Development

- 10.1 To make action plan of skill development by estimating the skill of migrant labours.
- 10.2 To emphasize over the multiple development.
- 10.3 Verification and certification of the efficiency of labours.

#### 11. To develop the legal, statutory and financial literacy of the labourers

11.1 To provide information about the legal system of protection of their rights to the migrant workers.

- 11.2 Sensitization of all departments (revenue, panchayat, labor, police, health, food, education, etc.) related to migrant labor.
- 11.3 To sensitize the conrtractors, employers and the labour organizations.
- 11.4 To develop an understanding of the labour before migration on financial management, banking behavior, withdrawal from ATMs, mobile banking, wage rate and payment book.
- 11.5 Awareness Dissemination of information related to the protection of migrant labor through communal propaganda.

#### 12. Establishment of 'Migrant Workers support Center' (Labuor Resource Center)

- 12.1 To operate the 'Migrant Workers Assistance Center' (labour resource center) at the development and district level to help the migrant workers.
- 12.2 In order to operate the labor resource center, a Shram Mitra Cadre will be prepared at the local level, so that the labour will work as entrepreneurs.
- 12.3 Labour registration, benefiting workers from projects, protection of migrant workers, and social security will be ensured through the Center of Labour Resources.
- 12.4 To make the legal, financial and social rights of the migrant workers aware by the labour resource center.

#### 13. Departmental Responsibility

It is necessary to ensure departmental accountability for the protection, awareness, skill development, and creating a healthy environment for the social workers of the migrant workers.

- 13.1 **Revenue Department** Under the migrant labour policy, the District Magistrate as a Nodal Officer, coordinating in various departments through all the revenue officers posted at the district level, taking action for the rehabilitation and welfare of migrant workers.
- 13.2 **Department of Panchayat and Rural Development -** Maintenance and updation of register of migrant labour and providing maximum employment under the schemes of government while rehabilitating the migrant workers at local level.
- 13.3 **National Development Authority** Estimation of skill, skill devekopment and certification of efficiency of migrant labour.
- 13.4 Employment and planning department, industry department and village industry department. To coordinate with various works department, industries to take up employment opportunities at the local level for the labourers.
- 13.5 **All Manufacturing Departments -** To encourage contractors of works department for providing work with priority to local labourers.
- 13.6 **Department of Education, Department of Primitive Development** To emphasise regular education facility to the identified children of the migrant laborers, prioritize the admission to children of migrant workers in residential schools and Identification of children migrated to other state and informing concerned states so that they can avail opportunity of admission at destination state.
- 13.7 **Health Department** To ensure the benefit of various health care schemes currently run by migrant workers and to provide medical services to working women and children of migrant labour family.
- 13.8 **Department of Women and Child Development -** Improved operation of Sakhi One Stop Center to increase the reach of migrant women.
- 13.9 **Home Department** To start the 'Migrant Workers Help Desk' at Police Station level through which statutory assistance to migrant labourers can be provided.
- 13.10 Labour Department To ensure better implementation of various labour laws prevailing for the protection of the interests of migrant workers and to work for the welfare of migrant workers through inter- state co-operation and co-ordination. Provide social security to workers by registering them.
- 13.11 **Urban Administration Department** Ward-wise maintenance and updating of migrant labour registers in slum/labuor settlements located in urban areas, ensuring the benefits of essential facilities, prevailing schemes and health facilities to labourers migrated from rural areas to urban areas.

13.12 **District Planning Committee** - Supervision of labour welfare at the district level by monitoring and assessing labour survey, registration, call center, labour resource center.

#### Work to be done on Destination

The workers are unorganized at the destination; live in small groups and in the absence of information or due to fear of getting losing of job/work face the exploitation & difficulties. In this situation, the information is provided in collaboration with the State Government or local organization for the purpose of increasing the manpower of the labourers and ensuring their security and facilities at the destination sites. Adequate efforts will be made through the information technology system.

#### 14. Participation of Labour Organizations/Trade Unions, Voluntary Organizations

14.1 Mazdoor Saathi Network - Workers in the respective states to assist the labour partner network in the state of labour at the destination, including active labour organization, trade union, voluntary organization, local administration etc. Partner network will be prepared through which the migrant labor will be assisted by establishing inter-state dialogue and coordination.

#### 15. Monitoring of Wage Rate and Payment

- Providing benefits of the prevailing labour laws of the migrant labour, received in the destination states, so as to maintain co-ordination with the administration of the concerned state.
- 15.2 Protection of the interests of migrant labourers in the destination state by sharing information of the migrant register maintained by the panchayat and urban body with the concerned state.

#### 16. Joint effort with destination state

- 16.1 Making efforts of negotiations/understanding with destination state by the state of Chhattisgarh for the interest of Safety and welfare of labourers.
- 16.2 Government of Chhattisgarh will be request to the Central Government and other migrant labour destination states that wherever the state of Chhattisgarh workers are working, they should be benefited by the schemes of the center & they will have the right to receive the services, facilities and benefits as per the migrant state.

#### 17. Emergency System

The migrant labourers are working in unorganized form at other places by leaving up their native residence, hence during various disasters, they need the help of the government.

The migrant workers mainly face circumstances like difficulties arising out of natural calamities including accidental death, hostage situation, workers' benefits not being given by the applicant, etc. Since the migrant workers remain unorganized and their work availability & arrivals are irregular, the help of the migrant labourers in a crisis situation is expected by the government. Therefore, there will be a coordination committee of the departments at district and state level, that will work by making a definite work plan to provide assistance to migrant labourers in emergency situations.

#### 18. Measures for Financial Resources

- 18.1 In the recovery of building and other construction cesses, the present gap will be identified and efforts are made to increase the gross tax collection of gap.
- 18.2 In addition to this, identifying and labeling the sources of other budgets so that adequate budget can be available for labour welfare.
- 18.3 To make additional provisions in the budget of the State Government for the welfare of migrant labourers.

This policy can be very useful to protect the welfare of the workers and their welfare, which is important in the implementation of all departments, voluntary organizations, and labour organizations. This policy will prove to be fulfilling its objectives.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.